



विधानसभा में आए बिना डीएससी पर आलोचना? सीएम चंद्रबाबू का वार्डएसआरसीपी पर हमला



(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने वार्डएसआरसीपी के सदस्यों द्वारा विधानसभा और विधान परिषद का बहिष्कार करने पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मंदिर जैसी विधानसभा का बहिष्कार करना देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनता की समस्याओं पर चर्चा करने से उन मुद्दों को महत्व और पहचान मिलती है। बुधवार को विधानसभा

लॉबी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि बाहर बैठकर वार्डएसआरसीपी के सदस्य चाहे जितना बोले, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। **"अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा": सीएम चंद्रबाबू** मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी किसी पूरी पार्टी को ऐसे

मंच का बहिष्कार करते नहीं देखा। वर्ष 1978 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू और जयराम रेड्डी ने विधानसभा में मजबूती से मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा कि 1989 से 1994 के बीच एन.टी. रामाराव कुछ समय के लिए विधानसभा में नहीं आए, फिर भी वे सभी पार्टी की ओर से विधानसभा में जाकर जनता के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि 2019 से 2024 के बीच जब उन्होंने सरकार को चुनौती देकर सदन से बाहर कदम रखा, तब भी

उनके विधायक अंतिम दिन तक संघर्ष करते रहे। **"कुल्हाड़ी पार्टी के नेता को राजनीति की जरूरत है?"** चंद्रबाबू ने कहा कि विधानसभा में जनसमस्याओं को लेकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए संघर्ष ने सभी को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इस उम्मीद से चुनती है कि वे विधानसभा में उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि "कुल्हाड़ी पार्टी" के नेता को राजनीति में रहने की जरूरत है क्या? उन्होंने आरोप लगाया

कि ग्रुप-1 अनियमितताओं को छिपाने के लिए वार्डएसआरसीपी के सदस्य विधानसभा में नहीं आ रहे हैं और बाहर बैठकर कै पर कीचड़ उछाल रहे हैं। **"हमने BC आरक्षण बहाल किया"** मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि "कुल्हाड़ी पार्टी" द्वारा कम किए गए ठेआरक्षण को उनकी सरकार ने बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। सीएम चंद्रबाबू ने आरोप लगाया कि "कुल्हाड़ी पार्टी" के नेता और उनके झूठ पर जनता न तो विश्वास कर रही है और न ही उन्हें महत्व दे रही है।



(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त : विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू फोटो जर्नलिस्टों को शुभकामनाएं दीं। "फोटोग्राफों से मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात": सीएम मुख्यमंत्री ने इतिहास को दर्ज करने और यादों को संजोकर रखने वाले फोटोग्राफरों की सराहना की। उन्होंने मानवीय अनुभवों को शानदार तस्वीरों

जर्नलिस्टों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों को शुभकामनाएं दीं। "फोटोग्राफों से मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात": सीएम मुख्यमंत्री ने इतिहास को दर्ज करने और यादों को संजोकर रखने वाले फोटोग्राफरों की सराहना की। उन्होंने मानवीय अनुभवों को शानदार तस्वीरों

के रूप में प्रस्तुत करने वाले फोटोग्राफरों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मीडिया और पेशेवर फोटोग्राफरों से मिलना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। उन्होंने फोटोग्राफरों के समर्पण, रचनात्मकता और निरंतर प्रयासों की सराहना की।

"हर तस्वीर एक यादगार पल को संजोकर रखती है"

मुख्यमंत्री ने कहा कि फोटोग्राफर अपनी तस्वीरों के माध्यम से कई अनकही कहानियों को आवाज देते हैं। उन्होंने कहा कि हर तस्वीर अपने वाली पीढ़ियों के लिए समय के एक यादगार पल को सुरक्षित रखती है। चंद्रबाबू ने दुनिया भर के फोटोग्राफरों को शुभकामनाएं दी और लोगों को जानकारी व प्रेरणा देने वाले यादगार पलों को और अधिक कैमरे में कैद करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की।

विशाखापट्टनम में डेटा सेंटरों पर आलोचना को मंत्री लोकेश का करारा जवाब

(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त: विशाखापट्टनम में डेटा सेंटरों को लेकर वार्डएसआरसीपी नेताओं की आलोचनाओं पर आंध्र प्रदेश के शिक्षा एवं आईटी मंत्री नारा लोकेश ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटरों के पानी के इस्तेमाल को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि AI आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए डेटा सेंटर बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि गूगल के निवेश से विशाखापट्टनम में अन्य आईटी कंपनियों की रुचि भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर इकोसिस्टम के 6-5 GW तक पहुंचने पर सालाना करीब 3 TMC पानी की जरूरत होगी। **"डेटा सेंटरों के लिए वह पानी डायवर्ट नहीं करेंगे"** मंत्री लोकेश ने कहा कि नई कुलिंग तकनीकों के इस्तेमाल से डेटा सेंटरों में पानी की खपत और कम होगी। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटरों को पानी पोलावरम परियोजना के औद्योगिक आवंटन के हिस्से से मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया



कि विशाखापट्टनम शहर के लोगों की पेयजल जरूरतों के लिए आवंटित पानी को डेटा सेंटरों की ओर डायवर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलावरम से विशाखापट्टनम शहर तक गुरुत्वाकर्षण आधारित जलापूर्ति 18 महीनों के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटरों के लिए अलग पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 ठें के थर्मल पावर प्लांट की तुलना में एक डेटा सेंटर को लगभग दसवां हिस्सा ही पानी चाहिए। **"इसी तरह विकसित किए जाएंगे डेटा सेंटर"** मंत्री लोकेश ने सवाल किया कि

थर्मल पावर प्लांटों में पानी की खपत के बजाय केवल डेटा सेंटरों के खिलाफ ही विरोध क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने डेटा सेंटर आवंटन के लिए 6.5 ठें की सीमा तय करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि 6.5 ठें डेटा सेंटर आवंटन का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों को ही प्राथमिकता देगी। मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि विशाखापट्टनम के लोगों की जल जरूरतों पर किसी तरह का असर डाले बिना डेटा सेंटरों का विकास किया जाएगा।

राजनीतिक पार्टी के गठन पर विजय साई रेड्डी का अहम ऐलान

तिरुपति, 19 अगस्त: पूर्व सांसद वी. विजय साई रेड्डी ने तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। विजय साई रेड्डी ने कहा कि उन्होंने जनता की समस्याओं और उनकी आवाज को विधानसभाओं में मजबूती से उठाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विजय साई रेड्डी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर जल्द ही महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी महीने विजयवाड़ा में अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप राजनीतिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि विजयवाड़ा में नई राजनीतिक पार्टी के गठन, उसके उद्देश्यों और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर स्पष्टता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से राज्य और देश में सूखे की स्थिति न रहे तथा पर्याप्त बारिश होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी लोगों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। विजय साई रेड्डी की ताजा टिप्पणियों ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में उनके आगामी राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विजयवाड़ा में होने वाली घोषणा में पार्टी के नाम, नीतियों, राजनीतिक उद्देश्यों और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर और अधिक स्पष्टता मिलने की संभावना है।

मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कई फायदे देगा: नारायण

(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त: नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण ने कहा कि मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने से कई फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मजबूत जनसमर्थन प्राप्त होगा। बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि

पार्षदों और कॉरपोरेटों का मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रभाव नहीं रहेगा। इससे दोनों को तेजी से निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव से दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लागू करने का भी अवसर मिलेगा। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा

कि मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष निवेशकों, उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसके अलावा, इन दोनों पदों पर राजनीतिक प्रभाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले मंत्री नारायण ने विधानसभा में

नगरपालिका कानूनों का चौथा संशोधन विधेयक पेश किया। संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए पेश किए गए इस विधेयक को विधानसभा में मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा। अब तक इन दोनों पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी।

वार्डएसआरसीपी शासन में ग्रुप-1 परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं: सीएम चंद्रबाबू

(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वार्डएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की ग्रुप-1 परीक्षाओं के संचालन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत चिह्न का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सेवाओं में अधिकारियों के चयन के लिए ग्रुप-1 परीक्षाएं भविष्य में ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों, इसके लिए चिह्न

उम्मीदवार इन नौकरियों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ऐसी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि जनता और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को इन मामलों को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा जवाबदेही का मंच है और यहीं से जनता को तथ्यों से अवगत कराने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों, इसके लिए चिह्न

में एक सख्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी। चंद्रबाबू ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच राज्य में विनाश हुआ, यह बात वह कई बार कह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने विभिन्न सरकारी पदों पर जनता का भरोसा खत्म करने का काम किया। चंद्रबाबू ने बताया कि 2018 में ग्रुप-1 सेवाओं के लिए अधिसूचना जारी होने पर 1.14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 325 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं

को कड़ी सुरक्षा और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ले जाया जाता है। ऐसे में राज्य का प्रशासन संभालने वाले अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली परीक्षाओं में इससे भी अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नियमों की अनदेखी की। चंद्रबाबू ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग्रुप-1 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल तरीके के बजाय मैनुअल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत को गुमराह करने के तरीके से हलफनामे दाखिल किए

गए। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद स्थिति सुधारने के बजाय हाई-लैंड में मूल्यांकन के लिए ६.19 करोड़ के कार्यदेश जारी किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालत के आदेशों के बावजूद साक्षात्कार आयोजित किए गए और नियुक्तियां भी की गईं। मुख्यमंत्री ने चिह्न के नियमों की अनदेखी करते हुए निजी व्यक्तियों को मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपने की आलोचना की। चंद्रबाबू ने आरोप लगाया कि ग्रुप-1 अभ्यर्थियों की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक, ड्राइवर, प्लंबर और सुरक्षा गार्डों से कराया गया।

”सीएम चंद्रबाबू ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई“:

वेलुगोंडा परियोजना के विस्थापित

(पैन पॉवर न्यूज): अमरावती, 19 अगस्त: वेलुगोंडा परियोजना के विस्थापित परिवारों ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने वेलुगोंडा परियोजना के कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया है। उन्होंने अधूरी वेलुगोंडा परियोजना को पूरा होने से पहले ही वार्डएस. जगन द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने को "दुनिया का आठवां अजूबा"

विस्थापित परिवारों को मुआवजे के चेक सौंपे। बुधवार को परियोजना के विस्थापितों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के चौबरे में उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें ६200 करोड़ के मुआवजे के चेक सौंपे। इसके बाद विस्थापित परिवारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। **"परियोजना के कार्यों के साथ विस्थापित भी महत्वपूर्ण": मंत्री निम्मला** आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री निम्मला रामानायडू ने कहा कि गठबंधन सरकार ने वेलुगोंडा परियोजना के कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया है। उन्होंने अधूरी वेलुगोंडा परियोजना को पूरा होने से पहले ही वार्डएस. जगन द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने को "दुनिया का आठवां अजूबा"



बताया। उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वार्डएस. जगन ने विस्थापित परिवारों को देय 900 करोड़ के मुआवजे में एक रुपया भी नहीं दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेलुगोंडा परियोजना को पूरा करना जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण विस्थापित परिवार भी सरकार के लिए हैं। उन्होंने



बताया कि विस्थापितों के लिए बनाई गई सात कॉलोनिमें में से चार में 100 प्रतिशत बुनियादी ढांचे का काम पूरा हो चुका है। बाकी तीन कॉलोनिमें में शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाएगा, मंत्री निम्मला रामानायडू ने कहा। **"विस्थापितों को बाकी 400 करोड़ जल्द देंगे":**

मंत्री डोला कल्याण मंत्री डोला श्रीबाला वीरांजनेय स्वामी ने कहा कि वेलुगोंडा परियोजना के विस्थापित परिवारों को दिया जाने वाला बाकी ६400 करोड़ का मुआवजा जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी अगस्त में नल्लमाला सागर में पानी छोड़ा जाएगा।

संपादकीय

मोदी को पता भी कि लालकिले से क्या बोला ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा जुमला इतिहास में उनकी याद का शायद एक और शब्द हो। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति, भारतीय मानस की शब्दावली में एक विचित्र नया लेवल जोड़ा-दिमागी नक्सल। मानती हूं, मेरे जैसे लोगों के लिए इस शब्द में एक खास तरह की गूंज है। भारत सके लोगों ने भी इसे पकड़ने में देर नहीं लगाई। चौबीस घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर गर्व से खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहने वाले लोग आ गए, रेंडिट पर इसके लिए अलग फ्लेयर की मांग होने लगी, दिमागी जनता पार्टी बनाने के मजाक चलने लगे, जबकि पी. चिदंबरम ने सीधे घोषणा कर दी कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। दरअसल राजनीतिक गालियों की एक दिलचस्प आदत होती है-वे अपने रचयिता के हाथ से तुरंत निकल जाती हैं। फिर दिमागी होना कोई सबसे बुरा आरोप भी नहीं है। आखिर सर्वप्रथम दिमाग तो है! लेकिन मजेगी को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और पहले उस मंच को देखिए जहां से यह कहा गया।स्वतंत्रता दिवस साल का वह एक दिन है जब प्रधानमंत्री केवल किसी पार्टी या सरकार के मुखिया की तरह नहीं, बल्कि गणराज्य की आवाज की तरह बोलता है। लाल किला वह जगह है जहां भारत खुद को देखता है-अपनी यात्रा, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी उम्मीदों को-और अपने लोगों से, और दुनिया से, यह कहता है कि वह अपने बारे में क्या मानता है। यही वह मंच है जहां से प्रधानमंत्रियों ने ऐसे शब्द छोड़े हैं जो अपने भाषणों से बड़े हो गए। नेहरू ने एक युवा भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक राष्ट्र-निर्माण की भाषा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया-जाय जवान, जय किसान-सैनिक और किसान, दोनों गणराज्य के केंद्र में। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा-विज्ञान भी वहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने इसी प्राचीर से भारत के ‘ज्ञान अर्थव्यवस्था’ में प्रवेश की बात की। कहा कि दुनिया में भारत की जगह ‘एए शोध और नई सोच’ पर निर्भर करेगी। इनमें कोई भी परिपूर्ण प्रधानमंत्री नहीं था, न उनके समय का भारत कोई परिपूर्ण भारत था। यह तर्क भी नहीं है। भारत ने हर रंग की सरकार में संसर्गित, असहिष्णुता और असहमति के दमन को देखा है। तर्क इससे कहीं संकरा और सटीक है-शब्दावली का। असल बात, उस खास मंच पर खड़े होकर कोई नेता राष्ट्रीय कल्पना में क्या रखता है? क्या बताता है? जवान, किसान, विज्ञान, ज्ञान, नई सोच-इनमें से हर शब्द ने किसी न किसी तरह राष्ट्रीय कल्पना का दायरा बढ़ाया। किसी नई भूमिका को सम्मान दिया, किसी नई क्षमता को विकसित करने का आग्रह किया, भारत क्या बन सकता है इसका एक और रूप सामने रखा। ‘दिमागी नक्सल’ इसका उलटा करता है।यह उस शब्दावली को नई नया जोड़ नहीं है। यह उसमें से कुछ घटाता है। लालकिले की इस परंपरा में पहली बार दिलचस्प पात्र वह भारतीय नहीं है जिसे बनने के लिए हमें कहा जा रहा है, बल्कि वह भारतीय है जिसे पहचानने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसे राष्ट्रीय कल्पना के भीतर लाया जाए, बल्कि कोई ऐसा जिसे उससे अलग किया जाए। और यह भारत के उसी मंच से कहा गया है जिसका अर्थ कम-से-कम उस सुबह सबके लिए बोलना होता है। दूसरा, इस वाक्यांश को किसी विषयधर की तरह नहीं, एक देशभक्त की तरह देखिए, तो इसमें कुछ गहरे स्तर पर अदेशभक्तिपूर्ण लगेंग। मैं यह शब्द पूरी गंभीरता से इस्तेमाल कर रही हूं। फिल्टले बारह वर्षों में ‘राष्ट्रविरोधी’ जुमला भारतीय राजनीति के सबसे आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले आरोपों में रहा है। प्रश्नकारियों पर, छात्रों पर, पत्रकारों पर, शिक्षाविदों पर, कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक विरोधियों पर। लेकिन राष्ट्रीय भावना के अधिक खिलाफ और क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री यह संकेत दे कि देश अपने सोचने वाले लोगों से ही सावधान रहे? भारत को इससे अधिक छोटा क्या कर सकता है कि भारतीय दिमाग-जिसे हम दुनिया के सामने अपनी ताकत के रूप में पेश करते हैं-उसे राजनीतिक संदेह की श्रेणी में बदल दिया जाए? भारत एक ऐसा देश है जिसे आज भी ज्ञान-शक्ति के रूप में जाना और सम्मान दिया जाता है। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के सीईओ हमें राष्ट्रीय उपलब्धि लगते हैं। कोई भारतीय वैज्ञानिक विदेश में सफलता हासिल करे तो हम गर्व करते हैं। कोई भारतीय गणितज्ञ सम्मानित हो, हमारे इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए निर्माण करें-हमें गर्व होता है। हम शून्य और आर्यभट्ट को याद करते हैं, नारंददा और तक्षशिला को भी। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां चाहिए, रिसर्च यूनिवर्सिटियां, पेटेंट, नोबेल पुरस्कार, स्टार्टअप चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी बार-बार भारत के युवाओं से कहते हैं-इनोवेट करो, डिस्प्ट करो, सपने देखो, बड़ा सोचो। और फिर आता है-दिमागी नक्सल। विरोधाभास मजेदार होता, यह वह इतना कुछ उजागर न करता। भारतीय दिमाग आविष्कार करे तो उसका उत्सव मनाइए। वही दिमाग सवाल पूछे तो बात जटिल हो जाती है। इसीलिए मैं बार-बार नक्सल से ज्यादा दिमाग पर लौटती हूं। राजनीतिक काल अंततः इतिहास का प्रमाण बन जाती है। वह आने वाली पीढ़ियों को केवल यह नहीं बताती कि किसी सरकार ने क्या किया, बल्कि यह भी कि उसने किस चीज की प्रशंसा की, उसने क्या कल्पना की और कई बार वह किससे डरती थी। और इसीलिए इस शब्द की परिभाषा का न होना महत्वपूर्ण है। आखिर दिमागी नक्सल है कौन? मोदी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नक्सली विचारधारा अपने दिमाग में रखते हैं, देश और युवाओं को गुमराह करने के मौके तलाशते हैं और उन्हें ‘पहचानकर अलग-थलग’ किया जाना चाहिए। लेकिन यह श्रेणी शुरू कहां होती है और खत्म कहां, यह नहीं बताया गया। जब भाषा साधारण राजनीतिक गाली की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो यह कोई छोटा सवाल नहीं है। और यह अस्पष्टता संयोग की नहीं है। यही इस शब्द की राजनीतिक उपयोगिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ऐसे कई शब्द दिए हैं। लेकिन यहां फर्क है। अर्बन नक्सल में कम-से-कम भूगोल था। आंदोलनजैवी के लिए कम-से-कम कोई आंदोलन होना जरूरी था। टुकड़े-टुकड़े गैंग में, कल्पनाशील ढंग से ही सही, किसी गैंग के होने का संकेत था। दिमागी नक्सल में किसी सदस्यता कार्ड की जरूरत नहीं। यहां भूगोल दिमाग के भीतर है। कुछ ही घंटों में दिख भी गया कि यह इलाका कितना फैल सकता है। एक छोर पर भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता’ दिखाई है-सबूत यह कि वे समारोह में मौजूद नहीं थे। दूसरे छोर पर एक भाजपा मंत्री की कहीं अधिक गंभीर व्याख्या टिप्पणी में घूमती रही-दिमागी नक्सल यानी माओवादी समर्थक, संविधान को भीतर से कमजोर करने वाला, अलगाववादी, ऐसा व्यक्ति जो अनुच्छेद 370 की वापसी चाहता हो या यहां तक कि उत्तर-पूर्व को भारत से उसके संकरे ‘चिकन नेक’ गलियारे के रास्ते काट देना चाहता हो। दूसरे शब्दों में-देशद्रोह, मानसिकता के कपड़ों में। लेकिन दोनों अर्थ एक साथ सही नहीं हो सकते। यदि किसी समारोह में अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति को उसी श्रेणी में डाल देता है जिसमें देश को दो हिस्सों में काटने की साजिश करने वाला व्यक्ति आता है, तो उस शब्द का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। और जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से लेने का दावा करती है, उसे इस शब्दावली को इतनी लापरवाही से खच करने वालों में सबसे आखिर में होना चाहिए। यदि दूसरा, अधिक गंभीर अर्थ ही असली दिमागी नक्सल है, तो सफ़ कहिए। देश को बताइए-कौन माओवादी हिंसा का समर्थन कर रहा है? कौन संविधान को नकार रहा है? कौन उत्तर-पूर्व को अलग करना चाहता है? और प्रमाण दीजिए। यह भ्रम मोदी सरकार को उसके आलोचकों से अधिक परेशान करना चाहिए। क्योंकि आज जो लोग सबसे असुविधाजनक सवाल पूछ रहे हैं, वे दिमागी नक्सल की इन दोनों परिभाषाओं में सहजता से फिट नहीं बैठते। इस गमी में लोक हनु प्ररीक्षा-पत्रों और अटक की भंतियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों ने यही दिखाया। यह समझने के लिए नरेंद्र मोदी और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान के पुराने रिश्ते को याद करना उपयोगी है। 2०14 में दिल्ली आए मोदी एक प्रतिष्ठान को चुनौती दे रहे थे। और उस चुनौती में दम था। भारत का पुराना बौद्धिक अप्रिजात वर्ग कई बार बेहद छोटा, बंद और खुद से असाधारण रूप से प्रसन्न रहने वाला था।

बुलडोजर न्याय: आम आदमी के लिए या भ्रष्ट तंत्र के लिए भी?



उत्तर प्रदेश में सरकारी काम कराने की भी एक अपनी अलग प्रणाली है। आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करने जाता है तो उसे धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि वह केवल काम कराने नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था के तौर-तरीके सीखने आया है। यहाँ ‘सुविधा शुल्क ‘, ‘फाइल गरम करना ‘, ‘काम की सेवा करना ‘, ‘फाइल भारी करना’ और ‘कुछ हमारा भी भला कर दीजिए’ जैसे शब्दों का अपना ही सरकारी शब्दकोश है। रिश्तत को रिश्तत कहने की जरूरत नहीं शब्द बदल दीजिए, व्यवस्था वही रहती है। फाइल पूरी है तो कोई कभी निकल सकती है। कमी नहीं है तो फाइल की चाल धीमी हो सकती है। चाल तेज करनी है तो किसी जानकार की जरूरत पड़ सकती है और जानकार मिल गया तो पता चलता है कि सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए आवेदन से ज्यादा जरूरी है व्यवस्था की जानकारी। कहीं यह काम सीधे होता है, कहीं दलातों के माध्यम से। दलाल भी बेचारा क्या करे उसने भी सरकारी व्यवस्था को समझकर अपना रोजगार बनाया है। आम आदमी लाइन में खड़ा रहता है और अनुभवी आदमी व्यवस्था की लाइन के बाहर से काम करवा लेता है। इन सबमें रोचक बात यह है कि यह व्यवस्था किसी एक विभाग की विशेषता नहीं है। विभाग बदल जाता है, मेज बदल जाती है, कुर्सी बदल जाती है, कर्मचारी बदल जाता है, बस काम कराने का तरीका कई बार वही रहता है। नैतिक शिक्षा देने वाले अधिकारी से लेकर चपरासी तक हर स्तर की अपनी भूमिका होने की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। यहां आम आदमी सरकारी दफ्तर में अपना वैध काम कराने जाता है और लौटते-लौटते उसे लगता है कि उसने काम नहीं कराया, बल्कि सरकारी व्यवस्था में एक लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। पहला पाठ, धैर्य रखिए, दूसरा पाठ-फाइल कहीं है, यह पूछते

रहिए।तीसरा पाठ, यदि काम बहुत जरूरी है तो किसी ‘जानकार’ को खोजिए और अंतिम पाठ व्यवस्था को समझे बिना व्यवस्था में काम कराना कठिन है। विडंबना यह है कि जिस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिक की सेवा करना है, उसी में नागरिक को कभी-कभी यह महसूस होने लगता है कि सेवा पाने के लिए पहले किसी की सेवा करनी पड़ेगी। आम आदमी अगर हिम्मत करके कहीं शिकायत कर दे, तो पहले तो यह तय नहीं कि उसका काम होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय हो जाता है कि उससे एक सवाल पूछ जाएगा-‘सबूत है?’ वह कहता है- ‘साहब, मुझसे पैसे मांगे गए हैं।’ जवाब आता है-‘ पहले साबित करो।’ बेचारा मन ही मन सोचता है-‘ मैं अपना काम कराने आया था या जांच अधिकारी बनने?’ अब उसे रिश्तत मांगने की आवाज रिकॉर्ड करनी है, अधिकारी का नाम-पता निकालना है, बैंक खाता खोजना है, जमीन-जायदाद का हिसाब लगाना है, रिश्तेदारों की संपत्ति तलाशनी है और फिर पूरी जांच की फाइल बनाकर विभाग में जमा करनी है। अर्थात सरकारी दफ्तर में काम कराने गया था, लेकिन लौटते-लौटते उसे जासूस, पत्रकार, लेखाकार और जांच अधिकारी-सब कुछ एक साथ बनना पड़ेगा। गरीब आदमी सोचता है कि भाई साहब, मेरे पास तो अपनी फाइल संभालने के पैसे और समय नहीं हैं, मैं अधिकारी की संपत्ति का सर्वे कैसे करूँ? और अगर शिकायतकर्ता के पास इतनी क्षमता, साधन और पहुंच होती कि वह खुद रिश्तत मांगने वाले अधिकारी के बैंक खाते से लेकर जमीन-जायदाद और रिश्तेदारों की संपत्ति तक की जांच कर सके, तो फिर सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियां किस दिन के लिए रखी गई हैं? व्यवस्था का कमाल देखिए-शिकायत आम आदमी करे, सबूत भी आम आदमी जुटाए, जांच भी आम आदमी करे और फिर कारोवाई के लिए भी वही दफ्तरों के चक्कर लगाए। सवाल बस इतना है कि अगर शिकायत करने वाले को ही पूरा मुकदमा तैयार करके देना है, तो फिर सरकारी जांच एजेंसियों का काम आखिर क्या बचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था ने भ्रष्टाचार से लड़ने का भी एक नया तरीका खोज लिया है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करो और साथ में उसी जांच की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर लेकर आओ! अरे भाई, यह भी मान लेते हैं कि हर शिकायत सही नहीं होती, झूठी शिकायत भी हो सकती है। लेकिन फिर जांच किसलिए है? शिकायत सही है या गलत, यह जांच से ही तो पता चलेगा। शिकायतकर्ता को ही जासूस, जांच अधिकारी और अभियोजक बना देना तो भ्रष्टाचार रोकने की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें भ्रष्टाचारी से ज्यादा शिकायतकर्ता परेशान हो जाता है। आखिर अगर आम आदमी को ही सबूत जुटाने से लेकर पूरी जांच

शिकायत। कहीं फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे की शिकायत। कहीं स्थानांतरण के नाम पर कमीशन की चर्चा। अब जनता भी बड़ी समझदार हो गई है। उसे पता है कि सरकारी फाइल के पैर नहीं होते, फिर भी कभी-कभी बिना तेल के चलती नहीं! यह व्यंग्य है, लेकिन शिकायतें गंभीर है। हर शिकायत को सच मत मानिए। लेकिन हर शिकायत को झूठ मानकर फाइल के नीचे दबा देना भी कौन-सा न्याय है? जांच कीजिए। गलत है तो शिकायतकर्ता को बताइए कि आरोप गलत थे। सही है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कम से कम जनता को यह तो महसूस हो कि उसकी शिकायत किसी सरकारी अलमारी में जाकर हमेशा के लिए समाधि नहीं ले चुकी है। सरकारी सड़क की कहानी भी कम मनोरंजक नहीं है। सड़क बनती है। कुछ समय बाद टूटती है। फिर मरम्मत होती है। फिर टूटती है। फिर नया बजट आता है। जनता सोचती है कि ‘सड़क बन रही है या सरकारी बजट को रोज व्ययाम कराया जा रहा है?’ अगर सड़क घटिया बनी तो केवल ठेकेदार से सवाल क्यों? जिसने निरीक्षण किया, जिसने गुणवत्ता प्रमाणित की, जिसने भुगतान मंजूर किया उनकी जिम्मेदारी भी तथ्य और कानून के अनुसार तय होनी चाहिए। करना ठेका कोई और लेगा, सड़क को कहां भी अगर बनाएा, बिल कोई और पास करेगा और टूटेंगी सड़क जनता की! अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द पर-बुलडोजर। आम आदमी के मकान पर बुलडोजर चलता है तो कानून की ताकत दिखाई देती है। जनता कानून के खिलाफ नहीं है। कानून जरूर चले। लेकिन जनता का सवाल है कि बुलडोजर आम आदमी की दीवार तक पहुंच सकता है तो भ्रष्टाचार की जांच बड़े अधिकारी की संपत्ति तक क्यों नहीं पहुंच सकती? यह मांग नहीं कि किसी अधिकारी की संपत्ति पर केवल आरोप लगते ही बुलडोजर चला दिया जाए। बिल्कुल नहीं। पहले जांच हो। सबूत सामने आए। कानून के अनुसार फैसला हो। दोष सिद्ध हो तो कार्रवाई हो। सरकारी कुर्सी भी जांच से बचने का प्रमाणपत्र नहीं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘शून्य सहनशीलता’ की बात करती है। जनता भी कहती है, बहुत अच्छी बात है। बस एक छोटा-सा निवेदन है कि शून्य सहनशीलता का शून्य नीचे वाले कर्मचारी से शुरू होकर ऊपर वाली कुर्सी तक भी पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि शून्य तो बहुत बड़ा लिखा हो और कार्रवाई का अंक उसके आगे लगने का इंतजार ही करता रह जाए! भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं हैं, सतर्कता विभाग है, लोकायुक्त है, शिकायत की व्यवस्था है। फिर शिकायतकर्ता से ही यह उम्मीद क्यों कि वह पूरा मामला बनाकर लाए? यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई मरीज अस्पताल जाकर कहे-‘डॉक्टर साहब, इलाज कर दीजिए।’ डॉक्टर

नागरिकों पर ही है शहर साफ रखने की जिम्मेदारी

सिर्फ सरकार को कोसना काफी नहीं। हमें खुद को भी आईना दिखाना होगा। अवैध निर्माण, मानकों से ज्यादा मंजिलें, नालियों में कचरा फेंकना, ये सब हम खुद करते हैं। ग्रामीण जीवन में जो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना थी, शहर आकर हम भूल गए। कहने को शहरी हैं, लेकिन व्यवहार जंगली जैसा। बरसात शुरू होते ही शहरों की गलियों-मोहल्लों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। मौसम

मूँदकर दी गई अनुमति। सड़क, नाली, सीवरज् कुछ भी सही न हो तो भी कॉलोनी पास। दूसरा, नालियों और सीवर में ठोस कचरा जमा होना, क्योंकि स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। तीसरा और सबसे खतरनाक, हर दो-तीन साल में सड़कों की ऊँचाई बढ़ा देना। जिससे आसपास के मकानों का तल हमेशा नीचे होता जाता है और पानी भराव की मुख्य वजह बन जाता है। पहले दो कारणों पर तो हर साल मीडिया में शोर मचता रहता है। लेकिन सड़क का बार-बार ऊँचा होना कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि

जितनी मोटी सड़क बिछाई जाएगी, ठेकेदार और इंजीनियरों का मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। पहली बार अच्छी गुणवत्ता की सड़क बना दी जाए तो बार-बार बनाने की जरूरत ही न पड़े। जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। तीसरा और सबसे खतरनाक, हर दो-तीन साल में सड़कों की ऊँचाई बढ़ा देना। जिससे आसपास के मकानों का तल हमेशा नीचे होता जाता है और पानी भराव की मुख्य वजह बन जाता है। पहले दो कारणों पर तो हर साल मीडिया में शोर मचता रहता है। लेकिन सड़क का बार-बार ऊँचा होना कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि

आज का राशि फल

मेष राशि: आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। वकीलों के लिये आज का दिन अच्छा रहेगा, नया केस हाथ लगेगा। आज खास लोगों के बीच किसी नई गतिविधि को लेकर गंभीर चर्चा होगी, जो कि सकारात्मक रहेगी। आज किसी मामले को लेकर विचारों में भावुकता रहेगी। आज कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना कर सकते हैं।**वृष राशि:** आज आपका दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज व्यवसायिक काम समय पर बनते जाएंगे। विदेश संबंध व्यवसाय में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने के आसार हैं। आज ऑफिस में सहयोगियों की कार्यकुशलता से तरगेट समय पर पूरा हो जाएगा।**मिथुन राशि:** आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जायेगा। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेंगी। आज रोजगार के कामों से हटकर कुछ नया सीखने में

अच्छा रहेगा। आज व्यवसाय में अतिरिक्त आय का साधन बनने वाला है। अगर आपका साझेदारी बिजनेस करने का प्लान है तो ये डील आपके लिए फायदेमंद होगी। अधिकतर समय मार्केटिंग और बाहर की गतिविधियों में बीतेगा। इस राशि के सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने कार्यभार से संतुष्ट रहेंगे। आपको घर के बड़े से कुछ प्रेरण मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, वो सफल होगा।**कन्या राशि:** आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज ध्यान करने पर उचित निर्णय लेने से समस्या आती है तो इसकी वजह

स्थिति रखेंगे तो आने वाली किसी समस्या से बच जायेंगे। इस राशि के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपकी ऑफिशियल यात्रा संभव है।**कुंभ राशि:** आज का दिन मिली-जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आपका दिन खुशनुमा बीगेगा। घर पर ही परिवारवालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभलकर करने की जरूरत है, आपके काम की शिकायत कर सकते हैं। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए।**मीन राशि:** आज आपको किसी अपने से अच्छे खबर मिलने के योग बने हुये है। आज व्यक्तिगत काम के समय आप घबराए की बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। परिवारिक सदस्य की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मार्केटिंग की जब कर रहे लोगों से आज अच्छा कलाईट जुड़ेगा।



पुष्करा लिफ्ट सिंचाई कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

रंपचोडवरम, पेन पावर, 19 अगस्त: पोलवरम परियोजना के तहत पुष्करा लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से लेफ्ट कैनाल में पानी पहुंचाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश पोलवरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने अधिकारियों को दिए। बुधवार को कलेक्टर ने देवीपट्टनम मंडल के नेलकाटा में जलविद्युत विभाग के इंजीनियरों के साथ जल डायवर्जन कैनल और पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लेफ्ट कैनाल तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइनों की स्थिति और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता मानकों के साथ कार्य पूरा



करने के निर्देश दिए। पाइपलाइनों से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत देने तथा कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

मतदाताओं की आपत्तियों पर कलेक्टर वेंकटेश्वर ने किया क्षेत्रीय निरीक्षण

तिरुपति, पेन पावर, 19 अगस्त: तिरुपति जिला कलेक्टर एस. वेंकटेश्वर ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों और आवेदनों की जांच प्रक्रिया का क्षेत्रीय निरीक्षण किया। उन्होंने सुल्लुरुपेटा विधानसभा क्षेत्र के ग्रहगुटा गांव में चल रही जांच प्रक्रिया का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाताओं की आपत्तियों और आवेदनों की नियमों के अनुसार पूरी तरह जांच कर निष्पक्ष तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी तरह



पारदर्शी होनी चाहिए और प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए। अपात्र प्रविष्टियों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आरडीओ वी. देवेंद्र रेड्डी, ओजिली तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एकलव्य स्कूलों की समस्याओं के समाधान में अब देरी नहीं

पाडेरू, 19 अगस्त (पेन पावर): अल्लूरी सीताराम राजू जिला कलेक्टर टी. निशांति ने अधिकारियों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में चिन्हित समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्कूल भवनों, पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने 31 अगस्त तक पेयजल से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणाम बेहतर बनाने के लिए



परीक्षा के माध्यम से 60 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर दुम्बिगुडा में विशेष प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया। कलेक्टर

ने कहा कि समस्याओं की पहचान तक सीमित न रहते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में हल किया जाए। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण



योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को आदेशों के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

एआई युग में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता

चौतन्य एमानी ने रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के तेजी से विकास के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। एआई का दुरुपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है, लेकिन इसी तकनीक के प्रभावी उपयोग से साइबर हमलों की पहचान कर उन्हें पहले ही रोका जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और आधुनिक तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

आधार पंजीकरण और अपडेट में तेजी लाएं: कलेक्टर कृतिका शुक्ला

नरसारावपेट, 19 अगस्त (पेन पावर): जिला कलेक्टर कृतिका शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रत्येक बच्चे का आधार पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित आयु पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाए। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर ने आधार से वंचित बच्चों की पहचान कर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। नरसारावपेट, पिडुगुराल्ला, दाचेपल्ली, गुरजाला और बोल्लापल्ली मंडलों में लंबित आधार पंजीकरण एवं अपडेट को एक माह के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने 5 दृ7 वर्ष और 15 दृ17 वर्ष आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक चौथे शनिवार को कलेक्ट्रेट में आधार शिविर आयोजित करने को कहा।



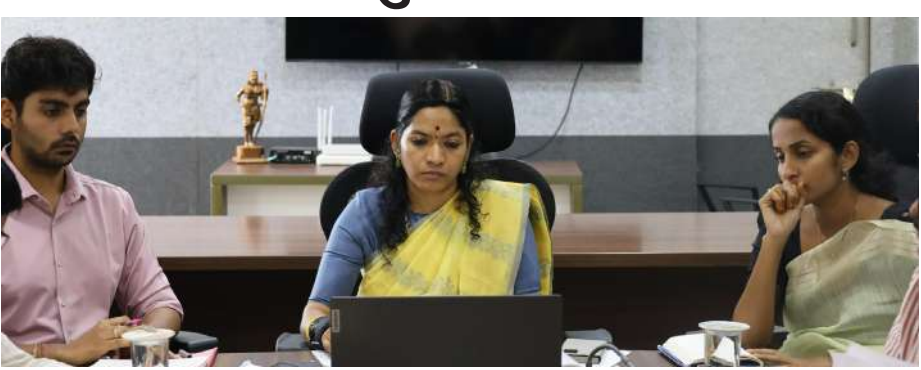
उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास

गंडेपल्ली, पेन पावर, 19 अगस्त: विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के साथ उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रगति यूनिवर्सिटी में उद्योग आधारित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित एआईदु3डी प्रिंटिंग कार्यक्रम, जीपीयू प्रोग्रामिंग स्पेशलाइजेशन इंटर्नशिप और नैसकॉम प्यूवरस्किल्स प्राइम असेसमेंट कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। प्रिंसिपल डॉ. जी. नरेश ने कहा कि विद्यार्थियों के रोजगार अवसर



पंचायत चुनावों के लिए पुख्ता तैयारियां करें

पाडेरू, पेन पावर, 19 अगस्त: आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुख्ता अग्रिम तैयारियां करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टरों को दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव पूर्व प्रक्रिया, मतदान, मतगणना, मतदाता विभाजन, मतदान केंद्रों की पहचान, कर्मचारियों की नियुक्ति, चुनाव सामग्री और प्रशिक्षण आदि पर समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया



कि चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं और आवश्यक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित समय में अपलोड की जाए। जिला कलेक्टर टी. निशांति, संयुक्त कलेक्टर तिरुमणि श्री पूजा, आईटीडीए पीओ आदित्य वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जिला प्रशासन तैयार



गुंदूर, पेन पावर, 19 अगस्त: जिला कलेक्टर सी.एम. साईकांत वर्मा ने कहा कि जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के लिए अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनीठ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले में चार शहरी स्थानीय निकाय हैं और मतपेटियों सहित अन्य चुनाव

सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। बैठक के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता सूची अपडेट करने, मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने, मास्टर ट्रेनरों की पहचान कर प्रशिक्षण

देने और चुनाव कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। संवैधानशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को भी कहा।

स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जिला प्रशासन तैयार: कलेक्टर कीर्ति चेकुरी

राजमहेंद्रवरम, पेन पावर, 19 अगस्त: आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूर्वी गोदावरी जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कीर्ति चेकुरी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा को तैयारियों की जानकारी दी। जिले के 21 मंडलों में 342 ग्राम पंचायतें और 4,040 वार्ड हैं तथा कुल 13,43,601 मतदाता हैं। ग्राम पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। कलेक्टर ने बताया कि एससी, एसटी और बीसी मतदाताओं की पहचान के लिए 18 से 22 अगस्त तक घर-घर सर्वे किया जाएगा और अंतिम सूची 7 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां भी की जा रही हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार गुलाबी और सफेद मतपत्रों की व्यवस्था भी की जा रही है।



स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुख्ता तैयारियां

बापटला, पेन पावर, 19 अगस्त: राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनीठ ने अधिकारियों को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुख्ता तैयारियां करने और मतदाता सूची प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंचायत, जिला परिषद, मंडल परिषद और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, बैलेट बॉक्स की स्थिति, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील केंद्रों की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था, चुनावी कर्मचारियों एवं



वट्टीचेरुकुरु तालाब के विकास कार्यों का निरीक्षण

गुंदूर, पेन पावर, 19 अगस्त: जिला कलेक्टर सी.एम. साईकांत वर्मा ने बुधवार को वट्टीचेरुकुरु गांव के तालाब में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 60 लाख की लागत से ये कार्य किए जा रहे हैं। तालाब को आकर्षक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां वॉकिंग ट्रैक, हरियाली, बेंच, बच्चों के खेलने के उपकरण और जिम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर ने जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों के प्रयासों की



सराहना की और तालाब का उचित उपयोग करने की अपील की।

'फ्रॉम पिंक टू पावर' पैनल में शामिल होंगी तापसी पन्नू सिनेमा में महिलाओं की रूढ़ियों पर होगी बात

अभिनेत्री तापसी पन्नू एक फिल्म फेस्टिवल में 'फ्रॉम पिंक टू पावर: ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप थ्रू सिनेमा' नाम के पैनल का हिस्सा बनने वाली हैं। अभिनेत्री का मानना है कि सिनेमा तब और दिलचस्प बन जाता है जब महिला किरदारों को पेचीदा और बेधड़क दिखाया जाता है। स्पेशल सेशन में शामिल होने पर अभिनेत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरे लिए, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना हमेशा एक रिस्क लेने और एक ऐसी महिला का किरदार अदा करने से हुआ है, जो शायद उस वर्जन में फिट न हो जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। इस सेशन में बात होगी कि कैसे सिनेमा गहराई से जमी हुई रूढ़ियों पर सवाल उठा सकता है।

कैसे ये पदें पर महिलाओं को दिखाने का तरीका बदल सकता है और दर्शकों को घिसी-पिट्टी कहानियों से आगे सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अभिनेत्री ने बताया कि फेस्टिवल में वे खुद



की जर्नी, करियर बनाने वाले फैसलों और पारंपरिक सोच से अलग हटकर काम करने के रिस्क के बारे में बात करेंगी। साथ ही वो ये भी बताएंगी कि सिनेमा के जरिए सवाल उठाना, लोगों को

सोचने पर मजबूर करना और प्रेरित करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, पिंक और थपड़ जैसी फिल्में एक बड़ी बहस का हिस्सा बनी थीं क्योंकि उन फिल्मों

में मेरे द्वारा निभाए गए किरदारों को एक तय संचे पर फिट करने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं हमेशा से मानती हूँ कि सिनेमा तब और ज्यादा दिलचस्प होता है, जब हम महिलाओं को कम कमजोरियों वाली, पेचीदा, महत्वाकांक्षी और बेधड़क अपने जैसी दिखाने की इजाजत देते हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में इन फैसलों और इनसे शुरू हुई बातचीत पर चर्चा करने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ।

यह फिल्म फेस्टिवल 20 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अभिनेत्री तापसी पन्नू की हाल ही में फिल्म अस्सी में नजर आई थीं। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में तापसी एक निडर वकील की भूमिका में हैं जो गैरप्रे सर्वाइवर को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती है।

'अगर देश से प्यार करना अंधभक्ति है तो मुझे गर्व है': ईशा कोप्पिकर

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने उन्हें दिए गए 'अंधभक्त' टैग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत से प्यार करना और उस पर विश्वास करना 'अंधभक्ति' कहलाता है, तो उन्हें इस लेवल को अपनाने में गर्व है। ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश के लिए कुछ करने की जरूरत पर बात करती नजर आईं। अभिनेत्री ने कहा, अगर अपने देश से प्यार करना, भारत पर विश्वास करना और उसकी तरक्की चाहना भक्ति है, तो हां, मुझे भक्त कहिए, अंधभक्त कहिए। लेकिन मेरी भक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने देश, अपने भारत के लिए है। राष्ट्र सबसे पहले है। ईशा ने कहा, ईसान जहां रहता है, उसे उस जगह का सम्मान करना चाहिए और उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि हमें अपने देश से प्यार है, देशभक्ति नहीं है। असली देशभक्ति तब है, जब कोई व्यक्ति अपने काम से देश को बेहतर बनाने की कोशिश करे।

अभिनेत्री ने बच्चों का उदाहरण देते हुए आगे कहा, "दो तरह के



बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी यह हिसाब लगाता रहता है कि उसके माता-पिता ने उसे क्या दिया और क्या नहीं दिया। वहीं दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो माता-पिता से मिलने वाली चीजों को सिर्फ अपने तक

सीमित नहीं रखता, बल्कि उससे अपने माता-पिता की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है।

ईशा ने कहा, "दोनों के बीच फर्क सिर्फ परिस्थितियों का नहीं, बल्कि सोच का है। इसी सोच को

देश के लिए भी बदलने की जरूरत है। हमें हर समय यह पूछने के बजाय कि देश ने हमें क्या दिया, यह सोचना चाहिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए कि अपने काम और सोच के जरिए भारत के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। अभिनेत्री ने आगे कहा, भारत बदल रहा है और अब समय आ गया है कि लोगों की सोच भी बदले। मेरी लोगों से अपील है कि वह नए भारत के निर्माण का हिस्सा बनें। मुझे भक्त कहिए, अंधभक्त कहिए या राष्ट्रवादी कहिए, मैं अपने विचारों को लेकर पीछे नहीं हटूंगी।

वीडियो के आखिर में ईशा ने भारत के प्रति अपने प्यार को दोहराते हुए कहा, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और भारत पर विश्वास करती हूँ। जय हिंद।

ईशा ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, अगर भारत से प्यार करना 'अंधभक्ति' है, तो मैं इस पहचान को गर्व से अपनाती हूँ। मुझे जो गलत लगता है, उस पर सवाल उठाती हूँ और जो सही लगता है, उसकी तारीफ भी करती हूँ। मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर रहेगा।

सामंथा रुथ प्रभु के लिए अब 'कंप्रेशन सॉक्स' ही हैं फैशन



अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई हैं और इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बदलते फैशन को लेकर एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, उन्होंने पैरों में पहने जाने वाले कंप्रेशन सॉक्स को ही अपना नया फैशन बता दिया। सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में उनके पैर सूजे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कंप्रेशन सॉक्स पहने हुए हैं। इसी तस्वीर के साथ सामंथा ने बेहद छोटे लेकिन मजेदार अंदाज में लिखा, "अब जिसे मैं फैशन कहती हूँ- कंप्रेशन सॉक्स।"

दरअसल, आमतौर पर फैशन को कपड़ों, जूतों और गहरनों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सामंथा ने अपनी मौजूदा स्थिति में आराम देने वाले सॉक्स को ही फैशन का नया नाम दे दिया। गर्भावस्था के दौरान पैरों और पंजों में सूजन की समस्या आम होती है। ऐसे में कंप्रेशन सॉक्स, पैरों में आराम देने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं।

दरअसल, सामंथा ने जून 2026

'108 बेस हॉस्पिटल-उरी' में एरिका फर्नांडिस का नया अवतार

'कसौटी जिंदगी की' और 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' जैसे सीरियल में अपनी अलग पहचान बना चुकी अभिनेत्री एरिका फर्नांडिस अपने नए शो '108 बेस हॉस्पिटल-उरी' में बिल्कुल अलग तरह के किरदार में नजर आ रही हैं। शो में वह डॉ. मेजर नैना का रोल निभा रही हैं। इस किरदार को लेकर उन्होंने काफी तैयारी की। उन्होंने अपने अभिनय के तरीके के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब वह सेट पर होती हैं तो पूरी तरह अपने किरदार में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही शूटिंग खत्म होती है, वह आसानी से उस किरदार को छोड़कर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आती हैं। एरिका फर्नांडिस ने कहा, मेरे लिए किसी किरदार में जाना और फिर उससे बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जब सेट पर पहुंचती हूँ, तो उस समय मैं अपने किरदार की दुनिया का हिस्सा बन जाती हूँ, लेकिन काम खत्म होते ही मुझे अपनी असल जिंदगी में वापस आना होता है। एक कलाकार के लिए शूटिंग के दौरान किरदार उसकी प्राथमिकता होती है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद वह खुद को उस भूमिका से अलग कर लेते हैं।

अभिनेत्री ने कहा, शो '108 बेस हॉस्पिटल - उरी' की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई खास सीन नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे शूटिंग खत्म होने के बाद अपने किरदार से बाहर निकलने में परेशानी हुई हो। शो में दिखाए गए मेडिकल केस जरूर काफी दिलचस्प थे और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कई मामले और परिस्थितियां ऐसी थीं, जो आम



जिंदगी से अलग थीं और इन्हें वजहों से शो का अनुभव मेरे लिए काफी अच्छा रहा।

एरिका ने अपने किरदार की तैयारी के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, डॉक्टर मेजर नैना को पढ़ें पर सही तरीके से दिखाने के लिए मैंने काफी रिसर्च की। करीब एक महीने तक मैंने मेडिकल से जुड़े कई शो और वीडियो देखे। इस दौरान मेरे ध्यान सिर्फ डॉक्टरों के काम पर नहीं था, बल्कि यह भी समझना था कि डॉक्टर किस तरह खड़े होते हैं, कैसे मरीजों से बात करते हैं और किसी गंभीर स्थिति में उनका व्यवहार कैसा होता है।

एरिका फर्नांडिस ने बताया कि वह अपने किरदार की तैयारी में इतनी ज्यादा शामिल हो गई थीं कि सेट पर मौजूद लोग उन्हें मजाक में 'डॉ. फर्नांडिस' कहने लगे थे।

उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बनने के लिए की गई मेरी मेहनत दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। मेरे लिए इस शो की खास बात यह भी रही कि मेडिकल केस और अलग-अलग परिस्थितियों के जरिए मुझे कई नई चीजें सीखने को मिलीं।

'108 बेस हॉस्पिटल - उरी' में एरिका के साथ गश्मीर महाजनी, निखिल खुराना, आयोशी तालुकदार, हितेश तेजवानी और रिमता बंसल भी अहम भूमिकाओं में हैं। मिलिट्री और मेडिकल दुनिया को साथ लेकर बनाया गया यह शो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ है। शो का प्रसारण हर शनिवार और रविवार को कलर्स और जियो हॉटस्टार पर किया जा रहा है।

रवि तेजा की 'इरुमुडी' को मिला यू/ए सर्टिफिकेट

साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक शिव निर्वाण की आगामी तेलुगू फिल्म 'इरुमुडी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने अब यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। यह एक गहन पारिवारिक और भावनात्मक ड्रामा है, जिसमें एक्टर रवि तेजा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मैथ्रू मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लीड रोल निभा रहे अभिनेता रवि तेजा की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, फिल्म 'इरुमुडी' को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है। इमोशनल फैमिली थ्रिलर के लिए टिकट बुक करने के लिए तैयार हो जाएं। 'इरुमुडी' 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शिव निर्वाण द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म में रवि तेजा, प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार और बेबी नक्षत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर (मैत्री मूवी मेकर्स) मिलकर फिल्म के निर्माण कार्य में

भूमिका अदा करते दिखेंगे।

फिल्म का शीर्षक 'इरुमुडी' भगवान अयप्पा की यात्रा और परंपरा से जुड़ा है। रवि तेजा इसमें एक आम और सहज पारिवारिक व्यक्ति के रूप



में दिखाई देंगे, जिन्होंने अय्यप्पा की माला पहनी

18 साल की उम्र में आमिर खान ने किया था सनी देओल के साथ काम, बोले- 'तब वह बड़े स्टार थे'

आमिर खान और सनी देओल आज हिंदी सिनेमा के उन बड़े नामों में शामिल हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। दोनों ने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं और अब सालों बाद एक बार फिर पड़ें से जुड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर साथ आए हैं। लेकिन इन दोनों कलाकारों का रिश्ता सिर्फ हाल के वर्षों का नहीं है। आमिर खान का सनी देओल से जुड़ाव उस समय का है, जब उन्होंने खुद बतौर अभिनेता बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। आमिर ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया और बताया कि वह महज 18 साल की उम्र में सनी देओल की फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके थे। आमिर खान ने यह खुलासा किंवद-आधारित रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में किया। इस खास मौके पर आमिर के साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा भी मौजूद थे। शो में जब दर्शकों के साथ सवाल-जवाब चल रहा था, तब आमिर से सनी देओल के साथ पहली बार काम करने के बारे में पूछा गया। इसी सवाल के जवाब में आमिर ने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि सनी देओल के साथ उनका पहला काम उस समय हुआ था, जब वह सहायक निर्देशक थे।

आमिर ने कहा, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मेरी शुरुआत एक सहायक निर्देशक के



तौर पर हुई थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात सनी देओल से हुई। मेरे चाचा और मशहूर फिल्मकार नासिर हुसैन उस समय 'मंजिल मंजिल' और 'जबरदस्त' नाम की दो फिल्मों पर काम कर रहे थे। दोनों फिल्मों में सनी देओल मुख्य भूमिका में थे, और मैं इन फिल्मों में सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी संभाल रहा था।

आमिर ने आगे कहा, मैंने करीब तीन साल तक सनी देओल के साथ सहायक के रूप में काम किया। उस वक्त मेरी उम्र महज 18 साल थी, जबकि सनी देओल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे और बड़े सितारे माने जाते थे। सनी जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने को लेकर मैं और मेरी टीम काफी उत्साहित रहती थी। मेरे लिए यह फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझने और सीखने का दौर था। आमिर ने जिस फिल्म का पहले जिक्र किया, वह फिल्म 'मंजिल मंजिल' साल 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था।

फिल्म में सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थीं। डैनी डे'जोंगा, प्रेम चोपड़ा

और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था, जबकि इसके गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म के 'ओ मेरी जान' और 'लूट गए हम तो राहों में' जैसे गाने भी लोगों के बीच लोकप्रिय हुए थे।

वहीं आमिर ने नासिर हुसैन की एक और फिल्म 'जबरदस्त' का जिक्र किया था, वह फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल के अलावा संजीव कुमार, जया प्रदा, राजीव कपूर, रति अग्निहोत्री, तनुजा और अमरीश पुरी जैसे कलाकार नजर आए थे। इसमें सनी देओल ने सुंदर कुमार का किरदार निभाया था, जो अपने परिवार और पिता के अतीत से जुड़े सच को जानने की कोशिश करता है।

अब सालों बाद आमिर खान और सनी देओल एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'बंटवारा 1947' से जुड़े। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं और आमिर खान इसके निर्माता हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई है।